उपसभापति : सूद के बारे में उन्होंने बता दिया है ।

श्री रामचन्द्र विकल : कब्जा होते हुए प्लाट क्यों दिया गया ? और जो कीमत बढ़ेगी बिल्डिंग की मंहगाई के कारण उस की जिम्मेदारी किस पर होगी ?

श्री दलबीर सिंह : लीगल कब्जा तो उनका नहीं है । वह तो इंक्रोचमेंट है ।

Houses for economically weaker sections of society

♦264. SHRI KALPNATH RAT: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what are the details of schemes drawn up for providing houses to the economically weaker sections of society during the Seventh Five Year Plan period ;

(b) what are the funds proposed to be allocated for the same ; and

(c) what is the number of people who are expected to be provided with housing facilities during the current financial year under the schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) Housing is a State subject and the State Govts. U. T. Admns. have been given full powers to formulate and implement Social Housing Schemes as per their needs and plan priorities. One of the schemes is exclusively meant for EWS under which sites and services at cost price are provided to the beneficiaries. A loan of Rs. 5000-/ per beneficiary is also given on concessional rates of interest.

(b) Central financial assistance is given to the States/U. Ts. in the shape of block loans and block grants without their being tied to any particular scheme or head ofdevelopment.

(c) 1,51,161 EWS families are expected to be provided housing units during the year 1985-86.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सातवीं योजना में रूरल एरिया के लिये और अरबन एरिया के लिये हर साल के हिसाब से कितने मकानों का बदान की योजना सरकार की है ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि छठी योजना में कितने मकान दिये हैं उस का उत्तर तो हम ने "सी" में दे दिया है कि 1,51,161 फैमिलीज को मकान प्रोवाइड किये गये हैं और सातवीं योजना में हमारे पास प्रस्ताव हैं लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं बता सकता कि कितने मकान हम बनायेंगे ।

श्री कल्पनाथ राय : सरकार के पास कोई योजना तो होगी कि सातवीं योजना में आप की प्लानिंग क्या है और आप कितने मकान अरबन और रूरल वीकर सेक्शन्स के लिये बनायेंगे ?

श्री दलबीर सिंह : आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उन के संबंध में सातवीं योजना में जो मकान बनाने का हमारा लक्ष्य है वह राज्य सरकारों और संघ सरकार के परामर्श से निर्धारित किया गया है, और छठी योजना में हम ने क्या किया है वह बता दिया है, लेकिन . .

उपसभापति : सातवीं योजना का ड्राफ्ट जब आयेगा तो आप को पता लग जायगा कि उस में क्या होने वाला है । उस समय आप को सब मालूम हो जायेंगा । श्री एस० एस० महापात्र ।

DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA : Madam, Will the Minister kindly tell us if he is aware of modern technologies in house building at a cheaper cost and if they can fit into the demand of the weaker sections ? Second, is he aware of the technology displayed in the last Trade Fair here only two weeks back, where

every system was demonstrated and probably a house can be built at the cost of Rs 5000 and can be taken from one place to another ? Is he aware of these technologies and is the Government working on these ?

श्री दलबीर सिंह : वैसे तो पहले 3000 की सीमा थी और जब उस को बढ़ा कर 5000 किया गया है। उस के बाद जैसा कि आप ने कहा है कि नयी टैक्नालाजी के आधार पर मकान बनाये जाने चाहिए तो हम भी कीन हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वीकर सेक्शन के लिए जो हाउसिंग समस्या है जितनी अरबन एरिया में है उतनी ही रूरल में है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में उसके लिए कुछ फंड हम एलाट करने जा रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई में जो 45 लाख लोग स्लम में रहते हैं उनके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने 50 करोड़ रुपया दिया हुआ है क्या इस बहुत ही कम एलोकेशन से हम उस स्लम का सवाल हल करने जा रहे हैं या नहीं ? यह एक सवाल है और दूसरा सवाल . . .

उपसभापति : एक का तो जवाब पा लीजिए ।

श्री विठ्ठल राव माधवराव जाधव : दूसरा सवाल भी साथ ही पूछ लेता हूं । घर कैसा रहना चाहिए इसकी कोई डेफिनिशन है ? जब स्लम की प्रोब्लम हम सोचते हैं तो देहात में जाकर देखते हैं कि बहुत से हरिजनों और गिरिजनो के घर जो होते हैं वह स्लम से भी खराब होते हैं । इसका कोई हमारे पास सर्वे है कि अरबन और रूरल एरिया के बारे में जो धनराशि हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं हाउसिंग के लिए, उसका क्या प्रोपोर्शन है ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो पूछा है रूरल एरियाज के बारे में, यह एक्चूअवली स्टेट सब्जेक्ट है । यहां से फंड एलोकेट हो जाता है अब उसके बाद प्रायरिटी का काम उनका है ।

उपसभापति : यह प्लानिंग मिनिस्टरी का काम है कि कितना पैसा देना चाहिए ।

श्री विठ्ठल राव माधवराव जाधव : 50 करोड़ रूपये से सारा स्लम कलीयर हो जायेगा ?

श्री दलबीर सिंह : हमने वहां के एनवायरनमेंट और सेनिटेशन के बारे में सोचा है । हम यह चाहते हैं कि वे वहां पर अच्छे से अच्छा रहें हम उसमें जरूर करने की कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा वातावरण मिले और उनको अच्छा रहने की सुविधा हो ।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA : Madam, in the matter of providing houses to the economically weaker sections, some States are doing better than the others. For example, Andhra Pradesh, according to the admission of the Union Government, is doing extremely well in constructing houses for the weaker sections. During the last one and a half years, 280,000 houses have been built by the Andhra Pradesh Government for the weaker sections. Recently, in a conference of the Housing Ministers, it was requested that Andhra Pradesh should be allotted more funds to go ahead with this programme and also to increase the loan content from HUDCO in order to meet the extra cost of building houses. Previously the cost was only Rs. 6000/- to Rs. 9000/-. But it is now more because of the escalation of cost. Will the Minister consider giving additional amounts to Andhra Pradesh to build more, houses ?

श्री दलबीर सिंह : आपने जो कहा है, आन्ध्र प्रदेश को वैसे तो हमारा हुडको भी फाइनेंस करता है । उसमें आपकी राज्य सरकार जितना पैसा खर्च करेगी उसके अनुसार हुडको से बराबर पैसा मिलेगा ।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : उपसभापतिजी, कमजोर वर्गों के लिए जो मकान बनते हैं उन मकानों के मैटिरियल की कीमत आज कल मंहगाई के कारण बढ़ती जा रही है। सरकार जो पैसा या सामान देती है, मैटिरियल देती है...

उपसभापति : यह उन्होंने पूछ लिया है। आप दूसरा पूछिए।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : मैं दूसरा ही प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि इसके कारण जो रद्दी सामान लगता है मकान रद्दी बनते हैं तो क्या सरकार कमजोर वर्ग के लिये बनने वाले मकानों की लागत में, पूंजी में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

श्री दलबीर सिंह : वैसे तो पहले तीन हजार का प्रावधान था लेकिन इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर जो माननीय सदस्य ने कहा है हमने इसकी राशि बढ़ा दी है।

SHRI JAGESH DESAI :' Madam, Deputy Chairperson, the Bombay city contributes more by way of Income-Tax, Corporation Tax, Excise and Customs Duty. The Income-tax and Corporate Tax of Bombay city is more than 50 per cent of what has been recovered from the rest of the country. In spite of that, the Government is neglecting the housing necessities of the people of Bombay and especially of those who are living in slums. There are lakhs of people belonging to the weaker sections who are staying in slums. As such, I request the Government that they should take up massive housing schemes so that the problem can be solved to some extent to the slum areas. I want to know whether the Government is launching any schemes and whether the weaker sections in the slum areas are provided with housing in the Seventh Five Year and what the allocation is for that for Bombay.

श्री दलबीर सिंह : श्रीमान, मैं यह कहना चाहूंगा कि शासन की जो नीति है उसमें बम्बई शहर के लिए किसी प्रकार की कोई उपेक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि बम्बई शहर की झोपड़पट्टियों की सहायता प्रदान करनी चाहिए। हम जरूर इसका ख्याल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Question No. 265.

*265. *[The questioner {Shri Jagadish Jani) was absent. For answer* vide *col.* 36-37

DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA : Madam, this question is regarding Orissa. If Mr. Jani is not there, can I put the question ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, you cannot. Question No. 266.

DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA : The Minister wants to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, I do not want him to speak. Question No. 266.

Losses Suffered By FCI

*266. PROF. C. LAKSHMANNA : Will *the:* Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what are the losses incurred by the Food Corporation of India during the last three years due to lack of adequate storage facilities ;

(b) what are the state-wise details of monthly intake of different foodgrains from the Central pool by the State Governments; and

(c) what are the proposals and schemes (i) for timely disposal and utilisation of surplus stocks left over with the Central and State Governments and (ii) for